Seventeenth Loksabha

>

Title: Motion for consideration of the Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Bill, 2020 (Bill passed).

माननीय अध्यक्ष: अब आइटम नंबर-19 लेते हैं ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, क्या यह आज बिज़नस में था? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हाँ था । आप बोल लेना अगर बोलना चाहें तो ।

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Sir, on behalf of Shrimati Nirmala Sitharaman, I beg to move:

> "That the Bill to ensure financial stability and promote competitiveness in Indian financial markets by providing enforceability of bilateral netting of qualified financial contracts and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय वित्तीय बाजारों में अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग की प्रवर्तनीयता का उपबंध करके वित्तीय स्थायित्व को सुनिश्चित करने और प्रतिद्वंदता का संवर्धन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कोई माननीय सदस्य इस विषय पर बोलना चाहता है?

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर**,** मैं बोलना चाहता हूँ । The Bill only covers close-out netting. The current Bill fails to provide other kinds of bilateral netting practices; for example, netting by novation. Netting by novation is a contractual agreement whereby parties agree that all contracts between themselves will be consolidated into a single contract as soon as each new contract is entered into. It reduces counterparty credit risk by affecting a discharge of each individual foreign exchange contract or other obligation as it is netted. If the Bill is intended to truly widen the scope of the netting practice in India, it could have included methods such as netting by novation and payment netting.

My second point is that there is potential for money-laundering and tax avoidance. Netting is allowed for transfer of money without actual transfer of money. Therefore, netting becomes a potential bidding ground for trade-based money-laundering and tax avoidance practices. How will the Bill help in regulating and offsetting this risk?

Thirdly, it is an overambitious move. It is claimed by the Principal Economic Adviser Shri Sanjeev Sanyal in an interview that this Bill will act as an enabler to the corporate default swap market. This in turn will help lay the necessary condition to set up a liquid Indian

corporate bond market. CDS is not a prerequisite for setting up a corporate bond market and there are major issues with regard to regulation and supervision of both the CDS and bond market which will not be mitigated by the introduction of this legislation. What provision has the Government made to address the regulatory issues arising due to the legislation?

My last point is about the impact on bank capital. This Bill may not have a significant impact on the capital of banks. The ratio of market trade to the loan book of public sector banks is not so high as to generate considerable capital-saving from bilateral netting. Thank you.

22.00 hrs

माननीय अध्यक्ष : कोई अन्य माननीय सदस्य इस पर विचार रखना चाहते हैं?

श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए कोरोना महामारी के दौरान हो रहे संसद के इस सत्र में वित्त मंत्रालय द्वारा लाए जा रहे द बायलेटरल नेटिंग ऑफ क्यूएफसी बिल, 2020 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी की प्रेरणा से और नेतृत्व से बिहार तरक्की के पथ पर अग्रसर है । बहुत सारे विकास के काम हुए हैं और हो रहे हैं । पिछले कई दिनों से केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को आर्थिक सौगात के कई पैकेज दिए जा रहे हैं । कल ही प्रधान मंत्री जी द्वारा रेल मंत्रालय की कई परियोजनाओं को दिया जाना है ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा 18.09.2020 को इस्लामपुर-नटेसर रेलखंड पर सवारी गाड़ी को हरी झंडी दिखा कर शुभारम्भ किया है । इस रेलखंड के चालू होने से नालंदा व गया जिले के 50 से अधिक गाँवों की 8 लाख से अधिक आबादी सीधे रूप से जुड़ जाएगी और अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा । सर, बिल का समर्थन करते हुए...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद ।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । The Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Bill, 2020 का बहुजन समाज पार्टी पूरे मनोयोग से समर्थन करती है । एज ए कॉन्सेप्ट यह बिल जो पार्टीज़ को फाइनेंशियल कान्ट्रेक्ट में इनेबल करता है, जो एक दूसरे के विवादों को सैटल करने में मदद करता है, यह बहुत ही प्रगतिशील बिल है । हमें पूरी की पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में यह देश में बिजनेस को और नेगोसिएशन्स को सैटल करने में काफी मदद करेगा । मैं आदरणीय मंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूँ और हमें विश्वास है कि आगे चलकर इसमें तमाम बिजनेसेस को और फायदा मिलेगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): सर, मैं इतना ही कहूंगा कि जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स मेन्टेन नहीं होते, बाद में उसमें झगड़ा होता है । एक पार्टी अलग कहती है, दूसरी पार्टी अलग कहती है । उसकी वजह से बैंकों का जो एनपीए बढ़ता है या बाकी सारी चीजों पर जो असर करता है, वह देख कर इस बिल का स्वागत करते हैं । इस बिल में जो प्रावधान किए हैं, उससे सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी हो जाए, ऐसी अपेक्षा करता हूँ । मैं फिर दोबारा इस बिल का समर्थन करता हूं । धन्यवाद

माननीय अध्यक्ष : श्री अनुभव मोहंती, आप भी दो लाइन में समर्थन कर दीजिए ।

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): सर, मुझे लगता है कि इस बिल से डिस्प्यूट सैटलमेंट में बहुत सुविधाएँ होंगी और वह ज्यादा आसान हो जाएगा । बाकी मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और सरकार का अभिनंदन करता हूँ । मैं आशा करता हूं कि पिछले दिनों में इस बिल से जो-जो समस्याएँ रही हैं, उन सब समस्याओं से पार होकर

आगे अच्छे दिन आने का इंतजार करेंगे और आपसे आशा और उम्मीद रखेंगे ।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से, तेलगु देशम पार्टी की तरफ से हम भी समर्थन की बात आगे बढ़ाते हैं ।

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रसून बनर्जी । बिलों पर सभी दलों का समर्थन होना चाहिए ।

श्री प्रसून बनर्जी (हावड़ा): सर**,** इस बिल पर पूरा समर्थन है । अच्छे से काम करना होगा । एक साथ मिलकर चलेंगे । मेरा पूरा समर्थन है । हम आप लोगों के साथ हैं । देश को बड़ा करने के लिए सब को मिल कर चलना चाहिए । यही सबसे बड़ी बात है । हम लोग सब मिलकर चलेंगे ।

श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी (नान्दयाल): सर**,** हम बिल को सपोर्ट करेंगे ।

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): स्पीकर सर, यह अच्छा बिल है और आशा करते हैं कि सरकार ऐसे अच्छे बिल लेकर आएगी । हम भी समर्थन करते हैं । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : कोई और दल का माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं । सभी दलों का समर्थन है । अब अनुराग जी, आप थोड़ा बिल के बारे में ब्रीफ कर दीजिए ।

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, I would first like to thank all the hon. Members for supporting the Bill in the interest of the country.

Sir, let me say that this Bill proposes to provide a firm legal framework for netting of qualified financial contracts. This was spoken about during the Budget Speech by the hon. Finance Minister. This is to resolve unambiguous legal framework for enforceability of close out netting reduces. It is going to reduce the net exposure and it would also reduce the credit exposure of banks and other financial institutions from gross net exposure resulting in the substantial capital savings.

Sir, why I am saying about capital saving is because in today's time, I think, it is very important for the banks and the financial institutions. That is why we have brought this Bill. If you look at the main four key points of this Bill, you will find that the legal enforceability for netting of qualified financial contracts which are bilateral in nature will be taken care of. It will take care of designation of certain type of regulated financial contracts as qualified financial contracts; third will be the mechanism for close out netting in the event of default and it will also take care of imposing limitations on administration practitioners to enable smooth and expeditious close out netting.

महोदय, यह केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के लगभग 50 देशों में इस तरह का लीगल फ्रेमवर्क है और हमने आईएसडीए, जो international swaps and derivatives association है, उसके ही मॉडल नेटिंग एक्ट को ध्यान में रखकर यह प्रपोज्ड ड्रॉफ्ट बनाया है । शायद यही कारण है कि आज सभी सदस्यों ने, अलग-अलग राजनीतिक दलों से, आज भारत के हित में, ताकि इससे जो लगभग सेविंग का अंदाजा है, लगभग 46 हजार करोड़ रुपये का उसमें दिखाया गया है । इसके अलावा इसका लाभ भी मिलेगा और जो जी-20 की रिकमंडेशन है, उससे भी इसकी स्ट्रेंगथनिंग होगी, मार्जिन सिस्टम के लिए ।...(व्यवधान) हाँ, वार्षिक होगी । इससे फाइनेन्शियल सिस्टम को लाभ मिलेगा ।

सभी माननीय सदस्यों ने इसको ध्यान में रखकर अपनी बात कही है । मैं आपके माध्यम से सभी दलों के सभी सदस्यों का एक बार फिर आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने इसका समर्थन किया है ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय वित्तीय बाजारों में अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग की प्रवर्तनीयता का उपबंध करके वित्तीय स्थायित्व को सुनिश्चित करने और प्रतिद्वंदता का संवर्धन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

खंड 2 से 11

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापन, श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन – उपस्थित नहीं ।

श्री के. सुरेश जी ने इस विधेयक पर संशोधन दिए थे, लेकिन वे अभी सदन में उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं सारे खंडों को एक साथ ले रहा हूँ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 11 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

पहली और दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी**,** अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए ।

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है**:**

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, दो-तीन दिन से आप सब जिसका इंतजार कर रहे थे, आप अविलंब लोक महत्व के विषय, शून्य काल का इंतजार कर रहे थे, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में माननीय सदस्य बैठे हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि वे सब अपने-अपने क्षेत्र के बुनियादी सवालों को उठाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं । मैं कोशिश करूँगा कि सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर मिले, पर्याप्त समय नहीं, समय केवल एक मिनट मिलेगा ।

Hon. Members, please conclude in one minute. सब तैयार हैं । क्या सब इस बात से सहमत हैं?

अनेक माननीय सदस्य : जी महोदय ।

माननीय अध्यक्ष : जिनकी लाटरी खुली है**,** पहले उनकी सूची लेंगे ।

श्री धर्मेन्द्र कश्यप ।